समृद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

जर्मनी के प्रथम चांसलर बिस्मार्क ने कहा था, 'राजनीति संभावनाओं की कला है।' यह कथन भारतीय राजनीति में भी परिलक्षित होता है। कई बार वह अनैतिक और अन्यायपूर्ण भी हो जाती है। बहुधा जैसे-तैसे करके शासन करना ही राजनीति का नियम बन गया है। चुनावी राजनीति भावनात्मक भी हो जाती है, जिससे भारत में राजनीति ने समय-समय पर तुच्छ राजनीतिक मुद्दों का सहारा लिया और जनमानस के व्यापक हितों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। एक बड़े कालखंड तक गरीबी उन्मूलन के स्थान पर 'गरीबी हटाओ' जैसी राजनीतिक प्रथा जारी रही। इससे एक ऐसी शासन व्यवस्था में वृद्धि हुई, जो समाज को निराशा और असंतुष्टि की ओर ले गई। इस प्रचलित राजनीतिक प्रथा को विकासात्मक शासन की व्यवस्था ने चुनौती दी। इस व्यवस्था ने राजनीति को विकास के द्वारा, विकास के लिए और विकास के माध्यम से एक उपकरण के रूप में नया सिद्धांत दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जन-जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली व्यवस्था की नींव रखने के लिए भारतीय राजनीति में विकास की भूमिका को पुनः परंतु नए तरीके से प्रस्तुत किया। अर्थशास्त्र की भाषा में विकास के इस माडल के लिए मूल्य-स्तर में परिवर्तन की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है, ताकि 'पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति' अर्थात् समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सके।

मोदी सरकार की इस दूरगामी दृष्टि से प्रेरणा लेते हुए योगी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु एक समग्र योजना की अवधारणा और इसके क्रियान्वयन की व्यापक रणनीति तैयार की। विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश की योजना बनाई। उदाहरण के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को न केवल आधारभूत संरचना के लिए, बल्कि विकास की एक स्थायी व्यवस्था के दृष्टिगत विकसित किया जा रहा है, जो सामाजिक उत्थान हेतु अति आवश्यक कनेक्टिविटी, रोजगार, सहायक उद्योगों

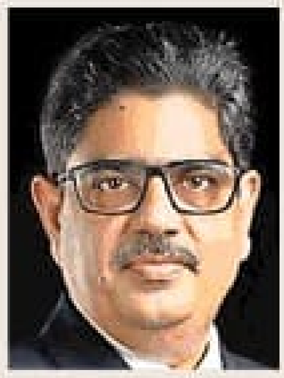

प्रो. आलोक कुमार राय

योगी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु समग्र योजना बनाने के साथ उसे धरातल पर मूर्त रूप भी दिया

अंत्योदय की संकलपना को साकार करते योगी • फाइल

की वृद्धि और समग्र भविष्य को तय करता है। राज्य सरकार ने शहरी ही नहीं, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत वितरण की निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की है जो आर्थिक सुदृढ़ता के सभी प्रयासों के लिए अति आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन प्रदान करने को बढ़ावा दिया है। यह न केवल विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, बल्कि उनकी उन्नत रैंकिंग और मान्यता से भी स्पष्ट हुआ है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग नौ करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था से उत्तर प्रदेश में स्वस्थ भारत का नवनिर्माण किया जा रहा है।

शिक्षा तथा कृषि को जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कृषि स्नातकों को ड्रोन तकनीक के द्वारा कृषि संवर्धन हेतु 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान स्वीकृत किए जाने की योजना बनाई। शिक्षा, खेल तथा रोजगार के संयुक्त विकास हेतु नई खेल नीति 2023 के तहत 172 राजकीय महाविद्यालयों में स्पोर्ट्स इन्फ्रा के निर्माण के साथ 132 खेल मैदान, 100 जिम तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 82 स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। स्वदेशी वस्तुओं के प्रोत्साहन तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना' और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' की शुरुआत की गई है, जिससे अब तक लगभग 5,000 इकाइयों की स्थापना हुई और एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। प्रदेश में हाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 32.92 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आने से लगभग 17 लाख नए रोजगार सृजन होने की संभावना है। हाल में राज्य सरकार ने 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत करते हुए एक ट्रिलियन डालर इकोनमी के लक्ष्य की ओर सुदृढ़ कदम बढ़ाए हैं। इसी प्रकार विकास दर को बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारी निवेश किया गया है। व्यापक नीतिगत सुधारों के तहत, शासन की भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था ने राज्य के कोष को समृद्ध किया है, जिससे आर्थिक विकास के आधार का विस्तार हो रहा है।

दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार ने विकास की प्राथमिकता के साथ दलितों, शोषितों एवं वंचितों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है और इसके लिए नित नई योजनाओ का सृजन किया। 15 करोड़ अंत्योदय और पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किसी विकासशील देश के लिए भी कल्पनातीत होगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णता के साथ लागू किया। एक ओर सामाजिक कल्याण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता तो दूसरी ओर विदेशी निवेश के लिए रेड कार्पेट, सरकार द्वारा अपनाए गए समाज के समग्र विकास के मूल मंत्र को प्रदर्शित करता है।

जनसंघ के संस्थापक पं.दीनदयाल उपाध्याय ने राजनीति को पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के साधन के रूप में देखा था। अंतिम व्यक्ति तक के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से संचालित विकासात्मक शासन, सरकार की सफलता के लिए अनिवार्य है। यह वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है, जो न केवल लोकतंत्र में राजनीति के स्तंभ को मजबूत करेगा, बल्कि राजनीति के मूल उद्देश्य को भी परिभाषित करेगा। इस व्यवस्था ने यह विश्वास बढ़ाया है कि उत्तर प्रदेश एक बेहतर, उज्ज्वल और समृद्ध प्रदेश बनने की दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं)

response@jagran.com